

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में "जल संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन" की आहूत बैठक दिनांक 05.03.2009 का कार्यवृत्त ।

स्थान: मुख्य सचिव सभा कक्ष

समय: सायं 4:00 बजे

उपस्थिति: (संलग्नक के अनुसार)

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यों में प्रगति लाने हेतु मिशन की बैठक शासनादेश संख्या 319/ ए.पी.एस./ स.प्र.जे.ज./ 2009 पेयजल विभाग देहरादून दिनांक 27 फरवरी, 2009 के क्रम में आयोजित की गयी ।

सर्वप्रथम सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत कर, पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की प्रगति प्रस्तुत करने हेतु मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान से अपेक्षा की गयी ।

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्यों में विभागों द्वारा जो प्रगति सूचित की गयी उसकी संकलित सूचना का प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण संलग्नक-2 के रूप में दृश्य है । प्रस्तुतीकरण में दो मुख्य बिन्दुओं को समाहित किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त जिन बिन्दुओं पर चर्चा की गयी और जो नीतिगत निर्णय लिये जाने की सहमति बनी उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय चरण में जल संस्थान द्वारा चिन्हित 500 जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यों हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित जल स्रोतों के Coordinates (Latitudes एवं Longitudes) के आंकड़े Global Positioning System (GPS) संयंत्र के माध्यम से ज्ञात कर इन आंकड़ों की सूची जलागम को उपलब्ध करायी जाये, जिससे उनके द्वारा Geographic Information System (GIS) में मैपिंग करायी जा सके। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने से यह ज्ञात हो सकेगा कि अमुक जल स्रोत का रिजर्व क्षेत्र, वन क्षेत्र में स्थित है अथवा नहीं। यदि Reserve Forest के अन्तर्गत उक्त स्रोत को चिन्हित किया जाता है तो Reserve Forest में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य करने हेतु वन विभाग को आवश्यक उपचार करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है । मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि राज्य में स्थित जल स्रोतों के चिन्हिकरण एवं उनमें वर्तमान जल उपलब्धता ज्ञात करने हेतु निष्पक्ष तृतीय एजेंसी (Consultant) की सेवा प्राप्त करके अध्ययन कराया जाय । यह निर्णय हुआ कि स्वजल द्वारा

(संलग्नक)

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसमें प्रथम चरण में इन 500 जल स्रोतों के आँकड़े जलागम को उपलब्ध कराये जायेंगे ।
(कार्यवाही: स्वजल) ।

2. अपर निदेशक, जलागम द्वारा अवगत कराया गया कि Remote Sensing Agency(RSA) के पास राज्य में स्थित समस्त Water Bodies का Data उपलब्ध है परन्तु यदि कोई तालाब सूखा हुआ है तो उक्त Data, Remote Sensing के माध्यम से उपलब्ध नहीं हो सकता है।
3. उपर्युक्त के अतिरिक्त जनपद, देहरादून के अन्तर्गत कार्लोगाड पेयजल योजना के अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य तथा बीजापुर कैनल के अप स्टीम में गुच्चूपानी नामक स्थान पर पेयजल योजना निर्माण हेतु शारान द्वारा क्रमशः रु० 30.25 लाख एवं 45.85 लाख कुल रु० 76.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत कार्य गतिमान है।
4. राज्य में स्थित जल स्रोतों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में, अपर निदेशक, जलागम द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य में स्थित समस्त जल स्रोतों का चिन्हीकरण कार्य तथा उनमें जल की उपलब्धता का सर्वेक्षण कार्य लगभग 02 वर्ष पूर्व कराया गया था जिस पर विस्तृत चर्चा भी हुई थी परन्तु अन्तिमीकरण अभी तक नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सम्बन्धित पत्रावली स्वजल को हस्तान्तरित की जा चुकी है। उक्त पत्रावली में राज्य में स्थित जल स्रोतों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध है । (कार्यवाही: स्वजल) ।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत की धनराशि जल स्रोत संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु मात्राकृत है एवं प्रत्येक जनपद में ग्राम स्तर पर जलस्रोत संरक्षण एवं सम्वर्द्धन के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, परन्तु उनकी सूचना मिशन में उपलब्ध नहीं है। अतः यह निर्णय लिया गया कि समस्त जिलाधिकारियों को यह पत्र प्रेषित किया जाये कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्रोत संरक्षण एवं सम्वर्द्धन सम्बन्धी जो कार्य किये गये हों उनकी सूचना प्रत्येक माह मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून को उपलब्ध कराई जाये, जिससे उनके द्वारा संकलित सूचना मिशन को उपलब्ध कराई जा सके। (कार्यवाही:समस्त जिलाधिकारी)

(अपराध)

बिन्दु-02

वर्षा जल दोहन (Rain Water Harvesting)

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नये भवनों के निर्माण में वर्षा जल दोहन (Rain Water Harvesting) टैंक बनाने का प्राविधान अनिवार्य रूप से करने के उपरान्त ही भवनों के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस बिन्दु पर चर्चा हुई कि इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि वास्तव में भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भवन स्वामी द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण किया गया है अथवा नहीं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि जिस प्रकार "पल्स पोलियो" अभियान के अन्तर्गत सतत मूल्यांकन किया जाता है उसी प्रकार इस बिन्दु पर भी मूल्यांकन किया जाना चाहिये कि प्रस्तावित रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य वास्तव में भौके पर किया गया है या नहीं। (कार्यवाही, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण)।

सचिव मा० मुख्य मन्त्री जी द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि इस बिन्दु पर भी विचार किया जाना चाहिये कि जो भवन स्वामी रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना को अपनाते हैं उनको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने की नीति पर भी विचार होना चाहिये। (कार्यवाही-विद्युत विभाग)।

सचिव, आवास द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि यदि नये भवनों के मानचित्र के अतिरिक्त किसी भी कार्य यथा-पूर्व निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार, सुदृढीकरण हेतु मानचित्र स्वीकृत कराया जाता है तो उक्त मामले में भी रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण अनिवार्य किया जाना चाहिये। इस बिन्दु पर भी विस्तृत चर्चा हुई कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण करने वाले भवन स्वामियों को Incentive दिया जाना चाहिये तथा जिन भवन स्वामियों द्वारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण नहीं किया जाता है उनके विरुद्ध Disincentive की नीति अपनाई जानी चाहिये। (कार्यवाही: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण)।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से यह अपेक्षा की गयी कि प्रथम चरण में पूर्व निर्मित शासकीय/ अर्द्धशासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण करने हेतु आगणन शासन से अलग बजट हैड में धन की मांग की जाये तभी इस कार्य में प्रगति आ सकती है। इस बिन्दु पर भी मत स्थिर हुआ कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को भी यह निर्देश निर्गत किये जाये कि शासकीय भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से तैयार करने हेतु बजटिंग की व्यवस्था के लिये प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय। मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि गढ़वाल एवं कुमायूँ

(स. सचिव)

मण्डल विकास निगम के समस्त भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना लागू किया जाना अनिवार्य होगा । (कार्यवाही: जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी) ।

बिन्दु-03

पेयजल गुणवत्ता:

मुख्य सचिव महोदय द्वारा पेयजल गुणवत्ता के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की गयी कि ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता बनाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय । (कार्यवाही: जल संस्थान, पेयजल निगम, स्वजल) ।

निदेशक, स्वजल द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के पेयजल विभाग के निर्देश पर राज्य में 09 पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है । निर्णय हुआ कि सचिव पेयजल की ओर से भारत सरकार को पत्र भेजकर प्रभावी कार्यवाही करायी जाय । (कार्यवाही: स्वजल) ।

मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जल संस्थान द्वारा वर्तमान में पेयजल की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु देश के कुछ राज्यों में 'सिल्वर आयोनाईजेशन' का प्रयोग किया जा रहा है । उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा भी कुछ नलकूपों पर इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है । इस तकनीक को जल संस्थान द्वारा भी अपनाये जाने पर विचार किया जा रहा है । इस विधि के द्वारा लगभग 48 घण्टे तक पानी बैक्टीरिया रहित रहता है ।

सचिव शहरी विकास द्वारा अवगत कराया गया कि 'एशियन विकास बैंक' (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित 03 शहर, देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में निर्माणाधीन योजनाओं में Water Analysis Lab के सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही की जा सकती है । इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अन्तर्गत भी Water Analysis Treatment Lab निर्मित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्यक्रम की अपेक्षित प्रगति हेतु राज्य जल संरक्षण एवं संवर्द्धन मिशन की मासिक रूप से बैठक आयोजित की जाय ।

Knostraw

अन्त में सचिव पेयजल द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

(महोदय)

(एम.एच. खान)

सचिव पेयजल

पृष्ठांकन संख्या 3351.....ए.पी.एस./स.प्र.जे.ज./2009 दिनांक 11 मार्च, 2009
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सज्जनार्थ ।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4. सचिव, सिंचाई / लघु सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन ।
5. सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन ।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, देहरादून ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून ।
10. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून ।
11. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून ।
12. मुख्य अभियन्ता-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
13. सीनियर इन्फोरमेशन ऑफिसर, एनआईसी, देहरादून को वेबसाईट हेतु ।
14. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड ।
15. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून ।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
17. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
18. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून ।
19. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी ।

(महोदय)

सचिव पेयजल

प्रतिवेदन
देहरादून

संख्या 3351 दिनांक 11-3-2009

नाम	पद नाम (विभाग)	टेलीफोन / Email	हस्ताक्षर
Shatrughna Singh Lehel-Mokem	Secy, Harapp CE-3 JWD	99979973 8 9412052088	SH 4
Sagar Chandra	CE & HOD Training	9411112472	S
M. P. Chauryal	CGM Jal Sansthan	9411110538	Chauryal
V. K. SINGH	GM Jal Sansthan	9411113817	Chauryal
S. R. Gupta	Secretary (Adm) Jal Sansthan	9411110601	G
S. K. Goyal	G.M., Regional Nigam	9411106722	G
H. S. Rawat	E.E. M.D.D.A	9412051700	L
P. S. RAWAT	EO M.D.D.A	9411108894	L
Ravi Pandey	EE, Nagar Nigam D'dm	9837256961 nagar-nigam2008 @yahoo.com	L
B. P. Gupta	CF, Yamuna Circle Front Dept.	0135-2745779 cf_yamuna_uta@yahoo.com	5/3/09
Keyul Lall	Director, 'Swajal'	9412087184	L
D. J. K. Sharma	AD WWD	wwd-va@aic-ia 9837007573	L
M. H. Khan	Sec. / D.W.		Chauryal
Anup Wadhawan	Secy, Forests and V.O.	anup_wadhawan @hotmail.com	Anup
B. K. Gupta	EE-Munor Irr	9412029879	BK
S. A. Anghwar	CE-MI	9412079153	L
P. M. Sundaram	VA, MDDA	9412056786	L
	Asst. Secy, Irrigation	9788440001	